



2026:AHC:124658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता संख्या - 4693 वर्ष 2026

अजय

बनाम

..... आवेदक(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमरेंद्र सिंह, विनायक पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से धारा 8, 20 मादक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 41 वर्ष 2026 पुलिस स्टेशन अछनेरा जिला आगरा में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और परोक्ष अभिप्राय के कारण वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को मौके पर ही गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के कब्जे से कोई वसूली नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त मुकदमे में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना का विरोध किया।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंततः यह धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त मुकदमे में, यह विचारण के निष्कर्ष तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह धारित की गई है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत विचारण तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विचारण के कार्यवाही को प्रभावित करने की संभावना, या साक्षियों को डराने सहित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मुकदमे के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुमति देना है या नहीं देना यह विवेक का मामला है।

6. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मुकदमे के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधि के सुस्थापित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, विचारण के लंबित तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला बनता है।

7. तदनुसार आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है।

8. आवेदक (गण)- **अजय**, को इस आदेश की एक प्रति के साथ आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, और उसे विचारण के निष्कर्ष तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक मुकदमे में निर्धारित दिनांक पर संबंधित अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराएगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं करेगा मुकदमे के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा करना ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा किया जायेगा।

9. मुकदमे में किसी भी शर्त के विफल होने पर आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

आदेश दिनांक: 2 जून 2026

एस.के.

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।